an>

Title: Regarding depleting ground water level in Jharkhand and need for rainwater harvesting.

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : महोदया, मैं आपके माध्यम से जल संरक्षण के लिए देशव्यापी आन्दोलन चलाए जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ। आजादी के समय देश में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 6042 क्यूबिक मीटर थी। जो वर्ष 2011 में कम होकर के 1545 क्यूबिक मीटर रह गई। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2015 में यह आँकड़ा 1340 क्यूबिक मीटर होगा। जबकि वर्ष 2050 तक यह आँकड़ा केवल 1140 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति ही रह जाएगा, जबकि देश की आबादी 1600 मिलियन को पार कर जाएगी। देश का लगभग 40 फीसदी हिस्सा पानी की गम्भीर समस्या से जूझ रहा है। हम अपने राज्य की बात करते हैं, जब झारखण्ड राज्य बना था, वहाँ 75 हजार कुएँ थे, आज की तारीख में केवल 10 हजार कुएँ बचे हैं। कई जगह भू-जल स्तर 1500 फुट तक नीचे चला गया है और भूगर्भ विभाग ने चेतावनी दी है कि महज 10 साल में ही जमीन के भीतर का पानी खत्म हो जाएगा। हालात यह है कि राजधानी राँची को पानी पिलाने वाले हटिया डैम में सिर्फ 20 दिन का पानी बचा है। पिछले दस साल में छह हजार करोड़ रूपए खर्च करने के बावजूद राज्य का जल संकट घटने के बजाय बढ़ता ही चला गया, क्योंकि जिम्मेदारी पदाधिकारियों ने केवल पानी निकालने के उपाय किए मगर रीचार्जिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया। जल संकट की सारी जिम्मेदारी किसी क्षेत्र पर डाल दी जाती है मगर सच तो यह है कि जल संकट गहराने में उद्योगों की भी अहम् भूमिका है, जो अधिकाधिक जल का इस्तेमाल कर दूषित जल नदियों में छोड़ देते हैं। विश्व बैंक भी मानता है कि कई बार एक फैक्ट्री एक बार में जितना पानी निकाल लेती है, गाँव एक महीने में भी उतना पानी यूज नहीं करता है।

माननीय अध्यक्ष : थोड़े में बोलिए, यह स्टेट मैटर भी है, स्टेट भी इसमें काम करेगा।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : वर्षा जल का संरक्षण और उचित प्रबन्धन ही जल स्तर सुधारने का एकमात्र उपाय है और यह तभी सम्भव है जब तालाबों का निर्माण हो और उनको पुनर्जीवित करने पर ध्यान दिया जाए। खेतों में सिंचाई हेतु पक्की नालियों का निर्माण किया जाए। बहाव क्षेत्र में बाँध बनाकर वर्षा जल को इकट्ठा किया जाए ताकि वह समुद्र में बेकार न जा सके। निजी बोरिंग ट्यूबेल पर नियंत्रण लगाया जाए और उन पर भारी जुर्माने की व्यवस्था हो ताकि पानी की बर्बादी रोकी जा सके।

मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर जल संरक्षण के लिए देशव्यापी अभियान चलाए और इस भयावह समस्या का निराकरण करने के लिए प्रयास करे क्योंकि "जल है तो जीवन है" कि हकीकत से हम भाग नहीं सकते। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री शरद त्रिपाठी, श्री सुधीर गुप्ता, और श्री रोड़मल नागर को श्री विष्णु दयाल राम जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।